सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की

क्रोध मूर्खों की छाती में ही बसता है।
-अल्बर्ट आइंस्टीन

मूल्य ₹ 3/-

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्षः 12 ● अंक 79 पृष्ठः 8 ● लखनऊ, शनिवार 25 अप्रैल, 2026

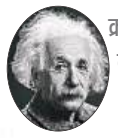

आरआर के खिलाफ फेल कमिंस की... 7 | नेताओं के बयान पर चारों ओर... 3 | भाजपा भूमाफिया की तरह कर... 2

आप साफ... ऑपरेशन लोटस की जद में सपा?

शिवसेना यूबीटी का दावा सपा पर बीजेपी की टेढ़ी नजर

» सात सांसदों ने बदले पाले लोकतंत्र फिर सवालों के हवाले?

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार के बाद क्या ऑपरेशन लोटस का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। शिवसेना यूबीटी जैसे राजनीतिक दल खुले मंच से कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस का अगला टारगेट उत्तर प्रदेश है और निशाने पर समाजवादी पार्टी है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस बाबत बड़ी खबरें सुनाई देगी। इस बात में दम इसलिए नजर आ रहा है कि यूपी बीजेपी के लिए सबसे खास है और समाजवादी पार्टी इसलिए निशाने पर है क्योंकि उसने ही बीजेपी के विजयी रथ को लोकसभा चुनाव में 35 सांसद जीतकर रोक दिया था।

यदि सपा ने इतनी बड़ी जीत यहां से दर्ज नहीं की होती तो यकीन जानिये मोदी सरकार में पहली बार जो बिल गिरा है वह न गिरा होता। बीजेपी को इस बात का मलाल है और शायद वह पहले से ज्यादा टफ या यूं कहें कि खतरनाक बन कर बैक करने की कोशिशें में लग चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी है। सत्ता के भीतर कई पावर सेंटर और जातिये गणित का ताना बना एटम बम का रूप ले चुका है। इसलिए इस बात की आशंकाएं बलवती हो रही है कि यूपी सपा में एक बड़ी घटना देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी को सीधी चुनौती देने के मामले में यूपी में सिर्फ सपा ही सामने हैं। बाकी राजनीतिक दल परास्त हो चुके हैं या फिर हथियार डाल चुके हैं।

> 2022 में हमारी शिवसेना को तोड़कर कैसे दो शिवसेना बनाई गयी? कैसे कई सारे सांसद और विधायक चले गए? वही आज आम आदमी पार्टी में हो रहा है और कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में होगा।

दीवार की तरह डंटे हैं अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी ऑपरेशन लोटस जैसे शब्द गूंजते हैं तो उनके पीछे सिर्फ आरोप नहीं होते एक डर भी होता है और एक रणनीति भी। सवाल यह है कि क्या हर राजनीतिक हलचल को इसी चश्मे से देखना चाहिए या फिर यह उस नेता की मजबूती का संकेत है जिसे रोकना आसान नहीं? यूपी में यदि विपक्षी मजबूत नेता को देखे तो अखिलेश यादव पर ही आकर नाम ठहरता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में वह चेहरा जिसने पिछले वर्षों में खुद को एक मजबूत विपक्षी धुरी के रूप में स्थापित किया है। अखिलेश यादव के इर्द गिर्द सियासी हलचल। उनकी पार्टी को लेर इतनी ज्यादा चर्चा? यह बताने के लिए काफी है कि यूपी राजनीति में बीजेपी को यदि किसी राजनीतिक दल से खौफ है तो वह अखिलेश यादव की पार्टी है। पिछले चुनावी नतीजों ने भी यह साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ने जमीन पर अपनी पकड़ को फिर से जीवित किया है। सामाजिक गठजोड़ को नए सिरे से जोड़ा है। युवाओं को अपने साथ मिलाने का काम किया है और एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया गया जिसमें क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय मुद्‌दे दोनों शामिल है। यह सच है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला अब एकतरफा नहीं दिखता। और यही बात किसी भी विपक्षी नेता की ताकत मानी जाती है कि वह मुकाबला पैदा कर दे। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनका युवा चेहरा और डिजिटल कनेक्ट है। उनका सामाजिक समीकरणों पर मजबूत पकड़ और सबसे अहम सीधी लड़ाई लड़ने की क्षमता।

क्या ऑपरेशन लोटस का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश है?

दो ध्रुव एक रण : यूपी में क्यों जरूरी है बीजेपी के लिए ऑपरेशन लोटस?

उत्तर प्रदेश की राजनीति अब धुंध से निकलकर साफ रेखाओं में दिखने लगी है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी जिसके पास मजबूत संगठन व्यापक संसाधन और राष्ट्रीय स्तर का स्थापित नैरेटिव है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो सामाजिक गठजोड़ क्षेत्रीय पकड़ और हालिया चुनावी प्रदर्शन से मिली ऊर्जा के साथ मैदान में है। यह सिर्फ दो दलों की लड़ाई नहीं बल्कि दो माडल, दो दृष्टिकोण और दो संदेशों की भिड़ंत है। बीजेपी अपने ट्रैक रिकॉर्ड कानून-व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र राज्य समन्वय को सामने रखकर स्थिरता का संदेश देती है। वहीं सपा सामाजिक समीकरणों की बारीक समझ स्थानीय मुद्‌दों की पकड़ और एंटी-इंकम्बेंसी के पॉकेट्स को साधकर संतुलन और बदलाव का नैरेटिव गढ़ती है।

बड़े नारों में नहीं छोटे-छोटे प्रबंधन में छिपा है राज

लेकिन इस बार असली खेल बड़े नारों में नहीं छोटे छोटे प्रबंधन में छिपा है। बूथ स्तर पर किसकी पकड़ मजबूत है? किसका कैडर आखिरी दिन तक सक्रिय रहता है? किसका उम्मीदवार स्थानीय समीकरणों में फिट बैठता है? यह सवाल कागज पर छोटे लगते हैं लेकिन चुनावी नतीजों में यही निर्णायक बनते हैं। और फिर आता है जनता का मूड जो हर इलाके में अलग है। पश्चिमी यूपी का समीकरण पूर्वांचल से अलग है बुंदेलखंड की प्राथमिकताएं अलग है और शहरी बनाम ग्रामीण मतदाताओं का झुकाव भी अलग अलग दिशा में चलता है। यही विविधता इस मुकाबले को और जटिल बनाती है। स्पष्ट है कि यूपी में अब बहुकोणीय लड़ाई नहीं रही। यह सीधी भिड़ंत है जहां हर कदम तौलकर उठाया जाएगा और हर चूक की कीमत चुकानी पड़ेगी।

> भाजपा को विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। भाजपा ने देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि उन्हें विपक्ष चाहिए ही नहीं।

जो आज आप में हुआ, वही कल सपा और कांग्रेस में होगा : आनंद दुबे

इस पूरे डरावने राजनीतिक वातावरण में शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता आनंद दुबे ने आने वाले कल की तस्वीर को रेखांकित करते हुए कहा है कि जिस प्रकार के ऑपरेशन लोटस के बारे में हमने सुना था 2022 में हमारी शिवसेना को तोड़कर कैसे दो शिवसेना बनाई गयी? कैसे कई सारे सांसद और विधायक चले गए? वही आज आम आदमी पार्टी में हो रहा है और कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में होगा। भाजपा को विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि उन्हें विपक्ष चाहिए ही नहीं। अगर 10 में से सात राज्यसभा सांसद आप में से भाजपा में शामिल हो गए तो उनके पास बचा क्या? उनकी पार्टी आम आदमी के लिए बनी थी लेकिन अगर उनके सदस्य ही राज्यसभा सांसद ही खास आदमी हो गए और सभी भाजपा में चले गए तो सवाल हमसे नहीं भाजपा से बनता है।

भाजपा भूमाफिया की तरह कर रही काम: अखिलेश

» सपा प्रमुख बोले- आग लगवाकर जमीन खाली करवाई जा रही

» लखनऊ के सभी तालाबों पर हो गया है कब्जा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ । सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर करार हमला किया है। सपा प्रमुख ने उसपर लखनऊ में भूमाफिया की तरह काम करने, जमीन कब्जाने और आग लगवाकर जमीन खाली कराने का आरोप लगाया। उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों की गेहूं खरीद और महिला आरक्षण पर भी सरकार को घेरा।

प्रेस वार्ता में कई मुद्दों पर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि राजधानी लखनऊ में भाजपा भूमाफिया बनकर काम कर रही हैं। कोई भी योजना आने के पहले भाजपा के लोग मिलकर पहले ही जमीनें ले लेते हैं। लखनऊ के सभी तालाबों पर कब्जा हो गया है। घटनाओं को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि जमीनें खाली करवाने के लिए भाजपा के लोग आग लगवा रहे है। जहां आग लग रही है, वहां समय पर न फायर ब्रिगेड और न एंबुलेंस पहुंच रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि महिला आरक्षण पर भाजपा के मन में खोट है। महिला आरक्षण पर झूठा प्रचार किया जा रहा है। महिलाओं को आरक्षण के साथ संरक्षण की जरूरत है।

भाजपा सरकार में बेटियों को नहीं मिल रहा न्याय

भाजपा सरकार पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि गाजीपुर से लेकर हाथरस और हरदोई तक बेटियों की हत्याएं हुई लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। हाथरस में बाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए भी दलों के लोग खड़े हुए लेकिन सरकार ने न्याय नहीं दिया। आरोप लगाया कि सरकार के लोगों ने दाह संस्कार के लिए परिवार को अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया जबकि सनातन धर्म में अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं रोकता है।

ग्रीन कारिडोर की डिजायन सीएम ने बनाई है

अखिलेश ने कहा कि लखनऊ में ग्रीन कारिडोर पर सात हजार करोड़ खर्च हो गया, लेकिन हर चौराहे पर ट्रैफिक रूका रहता है। ग्रीन कारिडोर की डिजायन ही खराब कर दी है। तंज कसते हुए कहा कि लगता है ग्रीन कॉरिडोर की डिजाइन इंजीनियरों ने नहीं मुख्यमंत्री ने बनायी है। पश्चिम बंगाल के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम यही से चैनलों के माध्यम से ममता बनर्जी के लिए प्रचार कर रहे हैं।

स्मार्ट मीटर खरीद में ही बड़े पैमाने पर हुई हेराफेरी

अखिलेश यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर खरीद में ही बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है। सरकार जनता की जेब से पैसा निकालकर उद्योगपतियों की जेब में डाल रही है। भाजपा सरकार ने जो सोलर प्लांट लगाया है, वह सिर्फ अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए लगाया है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोले कि सरकारी अस्पतालों, पीएचसी, सीएचसी में इलाज नहीं मिल रहा है। लीवर, किडनी और हार्ट के मरीजों को इलाज नहीं मिलता है। समाजवादी सरकार में बनाए गए कैंसर के रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी इस सरकार ने खराब कर दिया है।

प्राइवेट लोग खरीद रहे किसानों के गेहूं

सपा प्रमुख ने कहा कि किसानों के गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दे दिया गया है, वही गेंहू खरीद रहे है। किसानों के गेंहू खरीद को लेकर तरह-तरह की शर्तें लगाकर उन्हें उलझा दिया है। मार्केट में आटा बनाने के लिए दो-चार बड़ी कम्पनियां है वही सबसे ज्यादा गेंहू खरीद रही हैं।

बंगाल में एसआईआर हुआ फेल: केजरीवाल

रिकॉर्ड वोटिंग पर आप संयोजक ने कसा बीजेपी पर तंज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के खिलाफ राजनीतिक प्रतिक्रिया पनप रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में रिकॉर्ड मतदान के बाद मोदी जी की एसआईआर उन्हीं के खिलाफ जा रही है।

केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में यह बात सामने आ रही है कि लोग एसआईआर के खिलाफ मजबूती से वोट डाल रहे हैं। मोदी जी का एसआईआर उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनकी यह टिप्पणी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा गुरुवार को यह घोषणा करने के कुछ ही समय बाद आई कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में स्वतंत्रता के बाद से अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है, क्योंकि मतदान शाम 6

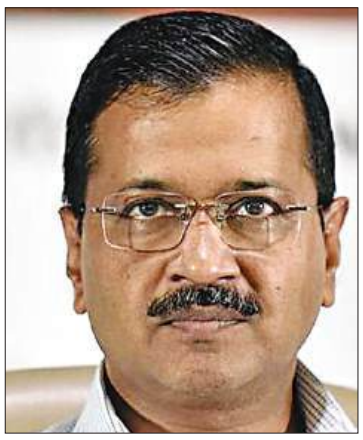

बजे समाप्त हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत - चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के प्रत्येक मतदाता को सलाम करता है। विधानसभा चुनावों के लिए मतदान गुरुवार शाम को समाप्त हो गया। भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण में तमिलनाडु के 84.80 प्रतिशत की तुलना में 91.91 प्रतिशत का उल्लेखनीय रूप से उच्च मतदान दर्ज किया गया। उच्च मतदान सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ, जिनमें दक्षिण दिनाजपुर में सबसे अधिक 94.85 प्रतिशत, उसके बाद कूच बिहार में 94.54 प्रतिशत, बीरभूम में 93.7० प्रतिशत, जलपाईगुड़ी में 93.23 प्रतिशत और मुर्शिदाबाद में 92.93 प्रतिशत मतदान हुआ। सभी प्रमुख क्षेत्रों में 9० प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ।

बसपा ने संगठन का पेंच कसना शुरू किया

» जयप्रकाश बसपा से फिर बाहर, पश्चिमी यूपी में बड़ा फेरबदल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ । बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी में पेंच कसना शुरू कर दिया है। पूर्व नेशनल कोआर्डिनेटर जयप्रकाश को पार्टी से फिर बाहर कर दिया गया है। बसपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के दिल्ली जाने के बाद बीते दो दिन में पश्चिमी उप्र के दो बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इससे पहले बृहस्पतिवार को सहारनपुर मंडल के जोनल प्रभारी हाजी सरफराज राईन को भी अनुशासनहीनता के आरोप निष्कासित कर दिया था।

जयप्रकाश सिंह के निलंबन का आदेश गाजियाबाद के पार्टी जिलाध्यक्ष मनोज कुमार जाटव ने जारी कर दिया, जिसमें कहा गया

है कि उनको बीते दिनों बसपा में वापस लेने के बाद भी उनकी पार्टी विरोधी मानसिकता नहीं बदली। साथ ही कार्यकर्ताओं से ऐसे स्वार्थी व अवसरवादी लोगों से सावधान रहने की अपील की है। बता दें कि आकाश आनंद के बाद जयप्रकाश की भी बसपा में वापसी हुई थी, जिसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य का प्रभारी बनाया गया था। केरल में विधानसभा चुनाव होने पर उनको वहां भेजा गया था। अचानक जयप्रकाश को पार्टी से बाहर करने से पार्टी में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी हैं।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

ममता का चौथी बार सीएम बनना तय: तेजस्वी

राघव चड्ढा के भाजपा में शामिल होने बोले राजद नेता- कुछ लोग डर से कर लेते हैं समझौता

» उत्तर 24 परगना जिले में सत्तारूढ़ दल के रोड शो में शामिल हुए तेजस्वी यादव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने विश्वास जताया है कि ममता बनर्जी लगातार चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। तेजस्वी उत्तर 24 परगना जिले में सत्तारूढ़ दल के रोड शो में शामिल हुए। यादव हां पहुंचे और जगद्दल, भाटपाड़ा तथा खड़दह विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो में शामिल हुए।

उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार अमित गुप्ता और जगद्दल से तृणमूल उम्मीदवार सोमनाथ श्याम के समर्थन में उत्साह एवं जोश के साथ रोड शो किया खड़दह विधानसभा सीट

से तृणमूल उम्मीदवार देवदीप पुरोहित के समर्थन में रैली में शामिल होने के बाद राजद नेता ने कहा, लोगों का अटूट प्रेम, दृढ़ विश्वास और व्यापक जनसमर्थन स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार चौथी बार प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। यादव के कोलकाता पहुंचने के बाद उनसे राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने को लेकर टिप्पणी के लिए कहा गया जिसके जवाब में उन्होंने कहा, कुछ लोग समझौता कर लेते हैं। वह डर या लालच के कारण भाजपा में शामिल हुए होंगे।

नेताओं के बयान पर चारों ओर घमासान

संवैधानिक संस्थाओं में भी बढ़ी हलचल

» कोर्ट ने टीएमसी नेता ममता को लताड़ा

» चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को दी नोटिस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। बंगाल व तमिलनाडु में 23 को वोटिंग से पहले संवैधानिक संस्थाओं में भी नेताओं के बयान व हस्पतक्षेप सियासी हलचल मचाए हुए थे। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व ममता बनर्जी निशाने पर रहीं। जहां ईडी जांच में सीएम ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के तर्कों को दरकिनार किया है। राज्य सरकार ने एजेंसी के मौलिक अधिकारों के तहत याचिका पर सवाल उठाया, लेकिन अदालत ने जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए मामले को गंभीर माना।

कोलकाता से जुड़े एक मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सख्त टिप्पणियां सामने आई हैं, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने की उस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने जांच एजेंसी की कार्यवाही के दौरान मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया था। बता दें कि यह मामला ईडी द्वारा कोलकाता में एक संस्था के अधिकारी के आवास पर की जा रही जांच से जुड़ा है। मौजूद जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने और कुछ दस्तावेज हटाए जाने के आरोप लगे हैं, जिस पर अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के पीएम मोदी को आंतकी बताने के बयान पर भाजपा ने उनके खिलाफ आयोग में शिकायत की। आयोग ने भी तुरंत उन्हें नोटिस भेजा। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आतंकवादी टिप्पणी का गंभीर संज्ञान लिया और इस मुद्दे पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह घटनाक्रम मंगलवार को तब सामने आया जब निर्मला सीतारमण समेत तीन केंद्रीय मंत्रियों के एक भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से संपर्क कर कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की।

राज्य के मुख्यमंत्री का जांच के बीच इस तरह पहुंचना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक : कोर्ट

गौरतलब है कि अदालत ने इस पूरे घटनाक्रम को असाधारण स्थिति बताते हुए कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का जांच के बीच इस तरह पहुंचना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई से लोकतंत्र पर खतरा पैदा हो सकता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मौजूद जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दलील दी गई कि जांच एजेंसी को सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों के तहत याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह एक सरकारी संस्था है, न कि कोई व्यक्तिगत नागरिक। साथ ही यह भी कहा गया कि इस मामले में पहले से ही उच्च न्यायालय में कार्यवाही चल रही है, इसलिए एक ही विषय पर अलग-अलग अदालतों में सुनवाई उचित नहीं है।

राज्य सरकार की ओर से दिए गए तर्क

गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को राज्य से सुरक्षा देना है, न कि सरकारी संस्थाओं को अधिकार देना। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की याचिकाओं को मंजूरी दी जाती है तो इससे भविष्य में संवैधानिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। वहीं, अदालत ने इन तर्कों पर कहा कि केवल कानूनी पहलुओं को ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि जमीनी हालात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में हाल के समय में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां अधिकारियों के साथ असामान्य व्यवहार किया गया, जो चिंता का विषय है। बता दें कि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब गुरुवार को होगी, जिसमें जांच एजेंसी अपनी दलीलें पेश करेगी। ऐसे में यह मामला न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम बन गया है और आगे आने वाले फैसले पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि इससे केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों की सीमाओं को लेकर भी स्पष्टता आने की उम्मीद की जा रही है।

खरगे विवादित बोल पर भाजपा का हल्लाबोल

राजनीति में बयानबाजी को लेकर एक नया विवाद सामने आया है, जहां सत्तारूढ़ दल और विपक्ष आमने-सामने नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। गौरतलब है कि यह शिकायत मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिए गए एक विवादित बयान को लेकर की गई है। मौजूदा जानकारी के अनुसार, निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने

एक चुनावी राज्य में प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो न केवल अनुचित है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि देश की जनता द्वारा चुने गए नेता के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग गंभीर मामला है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रतिनिधिमंडल में शामिल किरण रिजिजू ने भी इस बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत न करे। उन्होंने यह भी मांग की कि कांग्रेस और उसके अध्यक्ष को देश से माफी मांगने के निर्देश दिए जाएं। बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल में अर्जुन राम मेघवाल और अरुण सिंह भी शामिल थे। मौजूदा जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।

खरगे ने दे दी थी सफाई

वहीं, इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों और नेताओं पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि, बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनका आशय यह था कि प्रधानमंत्री अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर लोगों और राजनीतिक दलों को डराने का काम कर रहे हैं, न कि उन्होंने उन्हें सीधे तौर पर आतंकवादी कहा है। गौरतलब है कि देश में इस समय कई राज्यों में चुनावी माहौल बना हुआ है और ऐसे समय में नेताओं के बयान राजनीतिक बहस को और तेज कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी दौर में इस तरह के बयान विवाद को बढ़ा सकते हैं और राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकते हैं।

अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करना केजरीवाल को पड़ा महंगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के लिए अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा का हवाला देते हुए फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफार्मों को तत्काल संबंधित वीडियो हटाने का निर्देश दिया है, साथ ही इस मामले में अवमानना कार्यवाही की भी मांग की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही का वीडियो प्रसारित करने के संबंध में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने फेसबुक, गूगल और एक्स सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्च इंजनों को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई से संबंधित सभी वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। यह मामला आबकारी नीति से संबंधित है, जिसमें केजरीवाल स्वयं अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए थे।

न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ठेस पहुंचने की आशंका

अदालत ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही के वीडियो प्रसारित करने से न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए ऐसी सामग्री को तत्काल हटा दिया जाना चाहिए। आबकारी मामले में न्यायाधीश परिवर्तन की मांग वाली केजरीवाल की याचिका की सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के बयान और अदालत की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने वाले वीडियो को हटाने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत अरोरा की खंडपीठ ने पारित किया। वीडियो में केजरीवाल याचिका में केजरीवाल और अदालत की कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग भी की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा को हटाने की मांग की गई थी। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप किसी भी सबूत से समर्थित नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि ये चिंताएं केवल निराधार दावों पर आधारित हैं जो उनकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

खेल मैदान की बातें बहुत पर हकीकत कुछ और

पिछले कुछ सालों से गांवों में खेलों के मैदान की विकास के दावे बहुत किए गए। पर हकीकत में इन मैदानों पर या तो जंगली घास उगी या अवैध कब्जे हो गए है। भारत सरकार ने खेलों इंडिया के तहत गांवों की प्रतिभा को बड़े-बड़े मंचों पर पहुंचाने के लिए ग्रामीण स्तर पर खेल मैदान की कल्पना की थी। जो अब भी कागजों मे कल्पना ही रह गई है इस अव्यवस्था के लिए सरकारी मशीनरी की हीलाहवाली जिम्मेदार है। संसाधनों की यह कमी केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि उपकरणों के स्तर पर भी काफी चिंताजनक है। बजट का अभाव ग्रामीण विद्यालयों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। शिक्षा का अधिकांश बजट शिक्षकों के वेतन और मिड-डे मील जैसी अनिवार्य योजनाओं में ही समाप्त हो जाता है, जिससे खेलों के लिए नगण्य राशि बचती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में बसती है, जहाँ की मिट्टी ने मिल्खा सिंह, पी.टी. उषा और नीरज चोपड़ा जैसे महान खिलाड़ी दिए हैं। इसके बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में खेलों की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है।

विभिन्न शिक्षा रिपोर्टों और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आज भी लगभग 30 प्रतिशत से अधिक सरकारी स्कूलों के पास अपना स्वयं का खेल का मैदान नहीं है। जहाँ मैदान उपलब्ध भी हैं, वहाँ उनका रखरखाव इतना खराब है कि वे खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित नहीं माने जा सकते। बाउंड्री वॉल का न होना, मैदान में झाड़ियाँ उगना या स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण करना एक आम समस्या बन गई है, जिसके कारण बच्चों को सड़कों या संकरी गलियों में खेलने को मजबूर होना पड़ता है। संसाधनों की यह कमी केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि उपकरणों के स्तर पर भी काफी चिंताजनक है। बजट का अभाव ग्रामीण विद्यालयों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। शिक्षा का अधिकांश बजट शिक्षकों के वेतन और मिड-डे मील जैसी अनिवार्य योजनाओं में ही समाप्त हो जाता है, जिससे खेलों के लिए नगण्य राशि बचती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एक बड़े प्रतिशत स्कूलों में खेल के नाम पर केवल एक फटी हुई फुटबॉल या कुछ पुराने क्रिकेट बैट ही होते हैं। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या एथलेटिक्स जैसे खेलों के लिए आवश्यक नेट, पोल और ट्रैक तो ग्रामीण भारत के अधिकांश विद्यालयों के लिए आज भी एक विलासिता जैसे हैं। यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो प्रतिभाओं का दमन हो जाएगा।

“ भारत को वास्तव में एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनना है, तो हमें अपनी नीतियों के केंद्र में ग्रामीण विद्यालयों को रखना होगा। जब तक गाँव के हर स्कूल में एक समतल मैदान, आवश्यक खेल उपकरण और एक समर्पित कोच की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक फिट इंडिया और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना अधूरा ही रहेगा।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

मजबूत तूफान ले रहे भारत का इम्तिहान

गुरबचन जगत

भारत एक और चुनावी दौर से गुजर रहा है। राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मुद्दे राज्य और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों के हैं। चुनावों के बीच ही, केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में संसद में महिलाओं के लिए कोटा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन पर विवादित बिल पास करवाने की कोशिश की। इन कोशिशों का नतीजा जो भी हो, लेकिन इनसे राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय संकटों से हमारी अर्थव्यवस्था को खतरा बन रहा है। हमें गैस की कमी होने की आहट मिल रही है, जिससे रसायन, खाद, सिरेमिक, शीशा और वस्त्र उद्योग से लेकर आम रेस्तरां जैसे कामधंधे गहरे तक प्रभावित हो सकते हैं। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर हवाई किराये और इंडस्ट्रियल डीजल पर साफ दिखा है।

देश सांस रोके हुए है कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल-डीजल की कीमतें कहां जाएंगी। महंगाई अधिकांश घरेलू वस्तुओं को प्रभावित कर रही है, और आपूर्ति श्रृंखला में पड़े व्यवधान से प्रभावित हुई व्यवस्था में दुकानदार कीमतें बढ़ा रहे हैं। मध्य-पूर्व से बड़े पैमाने पर कारोबार करने वाले व्यापारिक घराने सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं। खाद उत्पादन और आयात में बड़े पैमाने पर रुकावट बनने से खाद्य आत्मनिर्भरता खतरे में पड़ गई है। खाड़ी देश अब वैश्विक खाद्य आर्थिकी का एक अभिन्न अंग हैं। लंदन यूनिवर्सिटी के 'सोअस' मिडिल ईस्ट इंस्टिट्यूट (स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज) के निदेशक एडम हनीह ने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा है—'खाड़ी मुल्क अब सीधे तौर पर खाद्य उत्पादन और वितरण श्रृंखला को स्वरूप देते हैं। वे आवश्यक रासायनिक घटकों के आपूर्तिदाता व बड़ी मात्रा में खाद निर्यातक हैं। जिन रास्तों से होकर मध्य पूर्व, केंद्रीय और पूर्वी एशिया के अधिकांश हिस्से की जरूरत का खाद्य एवं कृषि उत्पादन गुजरता है, उस पर उनका नियंत्रण है... खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का आसन्न परिणाम अकाल और खाद्य असुरक्षा है। इस सच्चाई का वजन उस दुनिया पर भारी पड़ने वाला है जो लड़ाई के असर को तेल की कीमतों में अस्थिरता के संकीर्ण चश्मे से देख रही है।'

यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब उद्योग-धंधे पहले से ही अमेरिका द्वारा लगाए भारी टैरिफ के प्रभावों से उबरने में जूझ रहे हैं। मार्च माह में भारत को मिले कच्चे तेल की औसत खरीद कीमत 125 डॉलर थी, जो मध्य-पूर्व में लड़ाई की वजह से बीच-बीच में 150 डॉलर तक पहुंची थी। यदि युद्धविराम

जारी रहे, तब भी कीमतें ऊंची बनी रहेंगी क्योंकि खाड़ी देशों के तेल उत्पादन-वितरण ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। इस परिदृश्य में महंगाई बढ़ना तय है, जब तक कि नई आपूर्ति लाइनें विकसित करने और कुछ पुरानी (रूसी) सप्लाई लाइनों को बहाल करने के वास्ते बड़े कदम नहीं उठाए जाते। जरूरत है युद्धस्तर पर राजनयिक संवाद पुन: स्थापित करने की, असफलता नुकसानदायक होगी। निस्संदेह, ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी से ज्यादातर दूसरी चीजों और सेवाओं की कीमतों में क्रमवार उछाल आना स्वाभाविक है, क्योंकि उत्पादन एवं परिवहन लागत पर काफी असर पड़ेगा। युद्ध के व्यवधानों से इकाइयां बंद हो रही हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका असर नोएडा में हाल ही में दिखा। इस स्थिति का इस्तेमाल दुश्मन ताकतें कर सकती हैं। इससे अर्थव्यवस्था को खतरा है; वहीं कूटनीतिक रूप से हम खुद को दलदल में फंसे पा रहे हैं। वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध भारत ने निर्णायक तौर पर जीता और विदेशी घुसपैठिए सैनिकों को खदेड़ा था। उस वक्त भारत को सशक्त राजनयिक समर्थन हासिल हुआ। विदेशी नीति एवं कूटनीतिक संबंधों में एक साथ सफलता मिली। रेखांकित करना चाहूंगा-उस साल जून में कोलोन शिखर वार्ता के दौरान, जी-8 ने पाक द्वारा एलओसी उल्लंघन करने की आलोचना कर भारत का समर्थन किया। यूरोपियन यूनियन ने भी पाक की ताड़ना की और क्षेत्र में भाईचारा बनाए रखने की भारतीय कोशिशों को सराहा। चीन ने तटस्थता बनाए रख दोनों पक्षों से एलओसी का सम्मान करने को आग्रह किया। तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कहा कि तुरंत बिना शर्त अपने सैनिकों को नियंत्रण रेखा से अपने इलाके में वापस बुलाए।

पुराने सहयोगी रूस ने, कूटनीतिक रूप से और सैन्य साजो-सामान से हमारा साथ निभाया। भारत को व्यापक समर्थन मिला और पाक अलग-थलग पड़ गया। प्रतिबंधों से आतंकवाद का प्रायोजक बनने तक सिमट गया। आज, वही दुनिया अलग है। जब अमेरिका ने ईरान के साथ वार्ता करनी चाही, तो उसने पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल की मदद ली। ईरान भी पाकिस्तान की भूमिका पर सहमत हुआ और मध्यस्थता स्वीकारी। पाक जनरल को व्हाइट हाउस में विशेष निमंत्रण पर बुला शराब-लजीज भोजन परोसा। उच्च श्रेणी में स्थान दिया।

स्त्रियों से राजनीतिक छल अब चलेगा नहीं

प्रमोद जोशी

भारत में महिला आरक्षण को लेकर एक साथ कई सवाल हैं। पहला है कि संसद में संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया, या उसे पास कराने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी? साफ है कि बीजेपी का इरादा इस मसले को उठाना, विरोधियों को उत्तेजित करना था, ताकि वे शोर मचाएं। भारतीय राजनीति विश्वसनीय नहीं है। सरकार जानती थी कि उसके साथ दो-तिहाई सदस्य नहीं हैं और आज के राजनीतिक हालात में उसे कतई आशा नहीं करनी चाहिए थी कि विरोधी राजनीति का कोई धड़ा उसके समर्थन में आता। तब फिर क्यों बिल पेश किया? फौरी तौर पर यह राजनीतिक तीर था, जो 'नारी-शक्ति' का लाभ उठाने के लिए चलाया गया था। संसद में जब बातें होती हैं, तब उन्हें गांव-गांव में सुना जाता है। विरोध में जितना शोर होगा, फायदा उतना ज्यादा होगा।

उद्देश्य माहौल बनाना, नैरेटिव रचना या इसे जो भी कहें, उतना ही था। विरोधियों की दिलचस्पी भी कम से कम महिला आरक्षण में नहीं थी। परिसीमन को लेकर भी उनके तर्क विचित्र थे। इससे ज्यादा उनका इरादा भी कुछ नहीं था। बहरहाल, इसका विपरीत-प्रभाव भी होगा, जो समूची राजनीति को अपनी चपेट में लेगा। क्या महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें छला जा रहा है? यह दीगर सवाल है कि इस विधेयक के परास्त होने का लाभ बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में मिलेगा या नहीं। असल बात यह है कि देश की राजनीति ने पिछले तीन दशक से 'नारी-शक्ति' को छला है। उसे बहुत ज्यादा छला नहीं जा सकेगा। स्त्रियों की राजनीतिक अभिलाषाएं आज उस सुप्तावस्था में नहीं हैं, जो नब्बे के दशक में थीं। साफ है कि यह विधेयक राजनीतिक-गतिविधि मात्र थी। जिस तरह से बिल के गिरते ही पोस्टर छपकर आ गए, और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की योजना बन गई, वह बताता है कि बीजेपी इसकी तैयारी के साथ आई थी। सबसे पहले एचडी देवेगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक, 1996 के रूप में 12 सितंबर, 1996 को महिला आरक्षण विधेयक, पेश किया था।

विधेयक पेश तो हुआ, लेकिन राजनीतिक आम सहमति न बनने और गठबंधन सरकार के भीतर विरोध के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा और 11वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही लैप्स हो गया। देश की राजनीति चाहती, तो देवेगौड़ा का बिल ही पास हो जाता। सरकार ने इसबार जो विधेयक पेश किया था, वह संसदीय सीटों के परिसीमन पर केंद्रित था। उसके विरोधियों का कहना है कि परिसीमन देश को तोड़ देगा। वे कहते हैं कि 2023 के बिल को लागू करो। वर्ष 2023 के महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, इसे परिसीमन के बगैर लागू नहीं किया जा सकता। यह कानून विशेष रूप से जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होने की शर्त से बंधा हुआ है। परिसीमन रुकेगा तो आरक्षण भी रुकेगा। सरकार ने 2023 के बिल की अधिसूचना जारी कर दी है, ताकि वह लैप्स न हो। उसकी प्रक्रिया ठीक से चली भी तो 2034 के चुनाव के पहले आरक्षण लागू नहीं हो सकेगा। संभव है कि 2039 में लागू हो।

क्या महिलाएं इतना लंबा इंतजार करेंगी? दरअसल, देश की पुरुष-संचालित राजनीति देख नहीं पा रही है कि महिलाएं धीरे-धीरे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर कर आ रही हैं। यह ताकत अभी तक वोटर के रूप में है, पर जल्द ही नेतृत्व के लेवल पर भी दिखाई पड़ेगी। जब 2023 का वह बिल पास हो रहा था, तब उसे लेकर जबर्दस्त सर्वानुमति थी। वह सर्वानुमति भी राजनीतिक-लाभ लेने तक की थी। उस वक्त भी सवाल था कि इसे फौरन लागू करने से रोका किसने है? कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में कहा था, जब सरकार नोटबंदी जैसा फैसला तुरत लागू करा सकती है, तब इतने महत्वपूर्ण विधेयक की याद साढ़े नौ साल बाद क्यों आई? बात तो बहुत मार्के की कही थी, पर दस साल तक कांग्रेस की सरकार रही, वह भी तो उसे लागू नहीं करा पाई। यूपीए के सहयोगी दल ही इसके लिए तैयार नहीं थे। 'इंडिया' ब्लॉक के नेता आज कह रहे हैं कि हम उस विधेयक का समर्थन करेंगे जो 543 सीटों की वर्तमान संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तुरंत लागू कराए। उन्होंने क्या सरकार के साथ बैठकर इस विषय पर बात की? जब वे जानते हैं कि जनगणना और परिसीमन के बिना यह फिलहाल कानूनी रूप से संभव नहीं है, तो उन्हें ऐसी पेशकश करनी चाहिए, जिसके पीछे ईमानदारी हो और व्यावहारिकता भी।

व्यावहारिक बात है कि सांसदों की वर्तमान संख्या को देखते हुए, किसी पार्टी का सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा में मोटे तौर पर 86 प्रतिशत पुरुष हैं और देश की विधानसभाओं में करीब 90 प्रतिशत। इसी संख्या पर आरक्षण लागू हुआ, तो बड़ी संख्या में पुरुषों का पत्ता साफ हो जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि उसका चुनाव-क्षेत्र आरक्षण के दायरे में चला जाए। भले ही एक-तिहाई सीटें महिलाओं के कोटे में जाएंगी, पर किसका क्षेत्र छिनेगा, पता नहीं। एक-एक चुनाव क्षेत्र को तैयार करने में बरसों की मेहनत और लाखों की रकम खर्च होती है। यह सब उन्हें मंजूर होता, तो 1996 से अब तक यह सब रुका हुआ क्यों है? बहरहाल, पुरुषों की इस राजनीति को महिलाओं की बढ़ती ताकत ही ठिकाने लगाएगी। अभी तक माना जाता था कि महिलाओं की राजनीतिक आवाज नहीं होती है। वोटर के रूप में उनकी आवाज को मान्यता मिल चुकी है।

मटके का पानी पाचन क्रिया को बनाता है बेहतर

गर्मी में सिर्फ पानी पीने के इच्छा होती है और ऐसे में फ्रिज का ठंडा पानी मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन यदि गर्मी में फ्रिज के बजाय मटके का पानी पिएंगे तो बहुत फायदेमंद होगा। मटका मिट्टी का बना होता है और मिट्टी के तत्व पानी में मिलने के बाद उसे और सेहतमंद बना देते हैं। मटके का पानी हर उम्र के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इस पानी से शरीर में होने वाली सभी गंदगी की दूर होती है। मटके का तापमान सामान्य से थोड़ा ही कम होता है जो ठंडक तो देता ही है, पाचन की क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आपको गैस या एसिडिटी की समस्या रहती है, तो ऐसे में रोजाना मिट्टी के घड़े का पानी पीना बेहद फायदेमंद रहेगा। क्योंकि इसके सेवन से पाचन क्रिया सुचारू रूप से कार्य करती है। इसे पीने से शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का स्तर भी बढ़ता है।

पीएच लेवल को करता है मेंटेन

मटके का पानी पीने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह पीएच लेवल मेंटेन करने में सहायता करता है। ऐसा मिट्टी में मौजूद क्षारीय गुणों के कारण संभव हो पाता है। मिट्टी के यह क्षारीय गुण पानी की अम्लता के साथ प्रभावित होकर, उचित पीएच संतुलन प्रदान करता है। मटके का पानी एसिडिटी और पेट दर्द जैसी समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है।

कैसे ठंडा करता है पानी

मिट्टी से बने होने के कारण मटके में अनेक सूक्ष्म छिद्र मौजूद होते हैं। आकार में बहुत सूक्ष्म होने के कारण इन छिद्रों को नग्न आंखों से देखना सम्भव नहीं होता। बता दें कि पानी का ठंडा होना वाष्पीकरण की क्रिया पर निर्भर होता है। जिसका मतलब जितना अधिक वाष्पीकरण उतना ज्यादा ठंडा पानी। इन सूक्ष्म छिद्रों द्वारा मटके का पानी बाहर निकलता रहता है और मटके में वाष्प बनाने के लिए गर्मी यह मटके के पानी से लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में मटके का तापमान कम हो जाता है और पानी ठंडा रहता है।

लू से भी बचाता है

अगर आप मटके का पानी पीते हैं तो इससे आप लू से बचे रहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं गर्मियों के मौसम में बहुत भीषण गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से लोगों को सनस्ट्रोक या लू लगना एक बहुत ही आम समस्या होती है। ऐसे में घड़े का पानी पीते हैं तो आपको लाभ मिलता है क्योंकि यह पानी विटामिन और खनिज शरीर के ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है जिससे शरीर को ठंडक मिलती है।

कैंसर के खतरे को कम करता है

मटके का पानी पीने से कैंसर की बीमारी का खतरा बहुत कम हो जाता है। घड़े का पानी गले से संबंधी बीमारियों से बचा कर रखता है और यह हमको जुकाम खांसी की परेशानी से भी बचाता है। मटके का पानी पीना से पीएच संतुलन सही होता है। मिट्टी के क्षारीय तत्व और पानी के तत्व मिलकर उचित पीएच बेलेंस बनाते हैं जो शरीर को किसी भी तरह की हानि से बचाते हैं और संतुलन बिगड़ने नहीं देते। मटके का पानी प्राकृतिक तौर पर ठंडा होता है, जबकि फ्रिज का पानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। बल्कि एक बड़ा फायदा यह भी है कि इसमें बिजली की बचत भी होती है।

वात, पित्त और कफ को करे नियंत्रित

बर्फीला पानी पीने से शरीर के तापमान में अचानक बदलाव आने लगता है। जिससे वात, पित्त और कफ बिगड़ने लगता है और सर्दी, खरास तथा कब्ज और अपच हो जाती है। वहीं मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होने के कारण किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता।

टॉक्सिक पदार्थों को अवशोषित करे मटका

मिटटी में मौजूद प्राकृतिक गुण पानी के सभी विषैले पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं और आपको एक साफ और मिरनलस से भरपूर पानी प्रदान करते हैं। साथ ही मटके का पानी ना बहुत अधिक ठंडा, ना बहुत गर्म होता है।

शरीर को ठंडक पहुंचाता है

अगर गर्मियों के मौसम में मटके का पानी पिया जाए तो यह शरीर को ठंडा रखने में बेहद मददगार साबित होता है। आपको बता दें कि मिट्टी के घड़े की सतह में छोटे-छोटे पोर्स होते हैं इनमें पानी आसानी से इवैपोरेट हो जाता है, जिससे उसकी गर्मी खत्म हो जाती है। इसी वजह से मटके में रखा हुआ पानी का तापमान कम हो जाता है। मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है जो शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करता है।

हंसना मना है

मरीज (डॉक्टर से)-मैं रोज 50 रुपये की दवाई ले रहा हूं, पर कोई फायदा नहीं हो रहा! डॉक्टर- अब तुम मुझसे 40 रुपये वाली दवाई ले जाओ, इससे तुम्हे रोज 10 रुपये का फायदा होगा!

टीचर- टिल्लू तुम बताओ, बड़े होकर क्या बनोगे? टिल्लू, शरमाते हुए- दूल्हा, टीचर- अरे मेरा मतलब है, बड़े होकर क्या पाना चाहते हो? टिल्लू, शरमाते हुए- दुल्हन, टीचर- उफ्फोह, मुझे बताओ, बड़े होकर ऐसा क्या करोगे जो तुमने अभी तक नहीं किया? टिल्लू- जी शादी!

टीचर- घर की परिभाषा बताओ, टीटू- जो घर हौसले से बनाये जाते हैं उसे हाऊस कहते हैं, जिन घरों में होम-हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं, जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं, जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं, जिन घरों के लोन के इंस्टॉलमेंट भरते-भरते आदमी लेट जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं, और जिन घरों में यह भी न पता हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। टीटू को student of the year चुना गया।

कहानी — अकबर का तोता

एक बार अकबर बाजार में भ्रमण पर निकले थे। वहां उन्होंने एक तोता देखा, जो बहुत ही प्यारा था। उसके मालिक ने उसे बहुत अच्छी बातें सिखाई थीं। उन्होंने उस तोते को खरीदने का फैसला कर लिया। तोते को खरीदने के बदले अकबर ने मालिक को अच्छी कीमत दी। वो उस तोते को राजमहल लेकर आए। यहां पर तोते को लाने के बाद अकबर ने उसे बहुत अच्छे से रखने का फैसला किया। अब अकबर जब भी उससे कोई बात पूछते, तो वह उस बात का तुरंत जवाब दे देता था। अकबर बहुत खुश हो जाते थे। वह तोता दिनों-दिन उनके लिए जान से भी प्यारा हो गया था। उन्होंने महल में उसके रहने के लिए शाही व्यवस्था करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सेवकों को कहा, 'इस तोते का खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा, 'यह तोता किसी भी हालत में मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर किसी ने तोते के मरने की खबर उनको दी, तो वह उसको फांसी दे देंगे।' एक दिन अचानक अकबर का प्यारा तोता मर गया। अब महल के सेवकों में हड़कंप मच गया कि आखिर अकबर को यह बात कौन बताएगा, क्योंकि अकबर ने कहा था कि जो भी तोते की मौत की खबर उन्हें देगा, वह उसकी जान ले लेंगे। अब सेवक परेशान थे। काफी सोच-विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि यह बात बीरबल को बताई जाए। सभी ने बीरबल को सारी बात बताई। यह भी बताया कि बादशाह अकबर मौत की खबर देने वाले को मौत की सजा देंगे। यह सुनकर बीरबल, बादशाह अकबर को यह खबर सुनाने को राजी हो गए। बीरबल ने कहा, 'महाराज एक दुखद खबर है।' अकबर ने पूछा- 'बताओ क्या हुआ?' बीरबल ने कहा, 'महाराज आपका प्यारा तोता, न तो कुछ खा रहा है, न तो कुछ पी रहा है, न तो कुछ बोल रहा है, न आंखें खोल रहा है और न ही कोई हरकत कर रहा है और न ही।' अकबर गुस्से में आकर बोले, 'न ही क्या? सीधा-सीधा क्यों नहीं बोलते कि वो मर गया है।' बीरबल ने कहा, 'हां महाराज, लेकिन ये बात मैंने नहीं आपने कही है। इसलिए, मेरी जान बक्श दीजिए।' अकबर भी कुछ न बोल सके। इस तरह बीरबल ने बड़ी सूझबूझ से अपनी और अपने सेवकों की जान बचा ली।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष — आय में वृद्धि तथा उन्नति मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। पार्टनरों का सहयोग समय पर प्राप्त होगा। यात्रा की योजना बनेगी। घर-बाहर कुछ तनाव रहेगा।

वृषभ — पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बनेगा। स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल रहेंगे। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। काम में मन लगेगा।

मिथुन — वाणी पर नियंत्रण रखें। चिंता तथा तनाव रहेंगे। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में निश्चितता रहेगी। लाभ होगा।

कर्क — दु:खद सूचना मिल सकती है, धैर्य रखें। फालतू खर्च होगा। कुसंगति से बचें। बेकार की बातों पर ध्यान न दें। अपने काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सिंह — आत्मसम्मान बना रहेगा। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। बड़ा काम करने का मन बनेगा। परिवार के सदस्यों की उन्नति के समाचार मिलेंगे। प्रसन्नता रहेगी।

कन्या — मित्रों का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। यात्रा की योजना बनेगी। प्रसन्नता रहेगी। घर-बाहर प्रसन्नतादायक वातावरण रहेगा।

तुला — आय में निश्चितता रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। बनते कामों में विघ्न आएंगे। चिंता तथा तनाव रहेंगे।

वृश्चिक — व्यवसाय ठीक चलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा मनोरंजक रहेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नौकरी में सुकून रहेगा।

धनु — सामाजिक कार्य सफल रहेंगे। मान-सम्मान मिलेगा। कार्यसिद्धि होगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। घर-बाहर प्रसन्नता का माहौल रहेगा। विवाद न करें।

मकर — किसी राजनयिक का सहयोग मिल सकता है। लाभ के दरवाजे खुलेंगे। किसी जानकार प्रबुद्ध व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। तंत्र-मंत्र में रुचि रहेगी।

कुम्भ — ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा खर्च होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चोट व दुर्घटना से बचें। आय में कमी रह सकती है। घर-बाहर असहयोग व अशांति का वातावरण रहेगा।

मीन — किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। परिवार के लोग अनुकूल व्यवहार करेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। नए लोगों से संपर्क होगा।

अहमद खान की फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आयेंगी शनाया कपूर

बॉलीवुड | गपशप

निर्देशक अहमद खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म के बाद अहमद एक जॉम्बी कॉमेडी फिल्म पर काम करेंगे। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ लीड हीरो के रोल में नजर आएंगे और उनके अपोजिट इस बॉलीवुड अभिनेत्री की एंट्री हो चुकी है।

वैरायटी इंडिया के अनुसार, इस जॉम्बी कॉमेडी फिल्म का निर्देशन अहमद खान करेंगे। फिल्म के निर्माता फिरोज नाडियाडवाला है। टाइगर श्रॉफ इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं। अब मुख्य अभिनेत्री के तौर पर शनाया कपूर का नाम सामने आया है। हालांकि, फिल्म को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म की बाकी डिटेल्स को अभी गुप्त रखा गया है।

शनाया कपूर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से की थी। उसके बाद उन्होंने आदर्श गौरव के साथ सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म 'तू या मैं' की है, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। अब वह अपने आगामी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। वहीं, टाइगर श्रॉफ अभी फिल्म 'लग जा गले' की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ जान्हवी कपूर और लक्ष्य मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले बन रही है।

अहमद खान की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल'

अहमद खान निर्देशित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में 30 से ज्यादा बड़े कलाकार काम कर रहे हैं। इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर और कई कलाकाल शामिल हैं। अहमद खान ने बताया कि इतनी बड़ी कास्ट को एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। अभिनेताओं की डेट्स, बजट और बाकी जरूरतों को संभालना आसान नहीं रहा। फिर भी उन्होंने यह फिल्म पूरी की।

सैयारा की सफलता के बाद फिर साथ आ रही सिंगर मिथुन और मोहित की जोड़ी!

बॉलीवुड की शानदार जोड़ी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन, डायरेक्टर मोहित सूरी एक बार फिर साथ आने वाले हैं। मोहित सूरी अपनी ब्लॉकबस्टर सैयारा के बाद एक बार फिर अपनी अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म पर काम कर रहे हैं।

द हॉलीवुड रिपोर्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म अहान पांडे और अनीत पड्डा की अपकमिंग लव स्टोरी है, जिसमें इमोशन्स और म्यूजिक दोनों का खास तड़का होगा। 'सैयारा' की सफलता के बाद यह टीम फिर से साथ आई है। इस नई फिल्म को भी एक इमोशनल और म्यूजिकल लव स्टोरी के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें गानों का काफी अहम रोल होगा।

खास बात यह है कि मिथुन पहले भी मोहित सूरी के साथ कई हिट गाने दे चुके हैं, और उनकी जोड़ी को म्यूजिक और रोमांस के लिए काफी पसंद किया जाता है। फिल्म को यश राज फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो इस नई जोड़ी को बड़े स्तर पर पेश करने की तैयारी में है।

सीधी बात करें तो, अगर आप दिल छू लेने वाली लव स्टोरी और शानदार म्यूजिक पसंद करते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए खास होने वाली है।

बॉलीवुड | मन की बात

मेरे करियर में मेहनत से ज्यादा भाग्य ने साथ दिया : अक्षय

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चाओं में हैं। फिल्म सिनेमाघरों में बनी हुई है। हाल ही में अक्षय कुमार का कहना है कि सफलता के लिए मेहनत जरूरी होती है। लेकिन मेरे करियर में मेहनत से ज्यादा भाग्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं अभिनेता अपने फिल्मी सफर को लेकर भी बात की। क्विज रियलिटी शो व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून को होस्ट कर रहे अक्षय कुमार ने मेहनत और भाग्य को लेकर अपनी राय रखी। शो में अक्षय ने कहा कि मैं अपने अनुभवों के आधार पर ऐसा मानता हूं कि मेहनत की जरूरत तो है और मैं पूरी लगन से मेहनत करता हूं। लेकिन मेरे करियर में या मेरी जिंदगी में भाग्य ने ज्यादा काम किया है। अक्षय कुमार ने फिल्म सेट पर अपने रोजमर्रा के अनुभवों के आधार पर आगे बताया कि उन्हें नियमित रूप से हजारों ऐसे युवा, महत्वाकांक्षी अभिनेता मिलते हैं जो उनसे अधिक प्रतिभाशाली या दिखने में बेहतर होते हैं। लेकिन फिर भी गुमनाम रह जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया है। अक्षय कुमार तीन दशकों से अधिक समय से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं और अब उनकी गिनती इंडस्ट्री के टॉप लीडिंग स्टार्स में होती है। उन्होंने लगभग 150 से भी अधिक फिल्में की हैं। इनमें कई ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्में रही हैं। इनमें हेरा फेरी, केसरी, जॉली एलएलबी, हाउसफुल और खिलाड़ी सीरीज जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय की भूत बंगला इन दिनों सिनेमाघरों में बनी हुई है। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म से अक्षय और प्रियदर्शन की हिट जोड़ी ने 14 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया हासिल हुई है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है।

चीन में क्यों खाया जाता है कॉकरोच इस कीड़े को खाने से नहीं आती घिन

जिस कॉकरोच को देखते ही हमारे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, जिसे हम गंदगी और बीमारी का प्रतीक मानते हैं, वही कीड़ा दुनिया के कुछ हिस्सों में स्वादिष्ट भोजन माना जाता है, यह सुनकर हैरानी होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारे घर के किसी कोने में जैसे ही यह दिखाई देता है, हम तुरंत उसे भगाने या खत्म करने के तरीके सोचने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस चीज से हम इतना घिन महसूस करते हैं, वही किसी और के लिए पसंदीदा डिश कैसे हो सकती है? चीन में कॉकरोच को सिर्फ मजबूरी में नहीं, बल्कि बड़े चाव से खाया जाता है। वहां के लोग इसे खास तरीके से पकाते हैं और इसे पोषण से भरपूर मानते हैं। कई जगहों पर तो कॉकरोच की खेती भी की जाती है, जहां इन्हें साफ-सुथरे माहौल में पाला जाता है ताकि इन्हें खाने के लिए तैयार किया जा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि चीन के लोग कॉकरोच को अपने खाने का हिस्सा बनाते हैं? क्या इसमें कोई खास पोषण होता है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस दिलचस्प जानकारी में आगे जानने को मिलेंगे।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के शीचांग शहर में एक दवा कंपनी हर साल लगभग 600 करोड़ कॉकरोच का पालन एक बड़ी इमारत में करती है। यह इमारत आकार में इतनी विशाल है कि इसे करीब दो फुटबॉल मैदानों के बराबर बताया जाता है। इस फार्म में कॉकरोच को खास तरीके से पाला जाता है। पूरी बिल्डिंग के अंदर हमेशा अंधेरा रखा जाता है और वातावरण को गर्म तथा नम बनाए रखा जाता है, ताकि उनके बढ़ने और प्रजनन के लिए सही माहौल मिल सके। यहां कॉकरोच को पूरी आजादी दी जाती है कि वे घूम सकें और तेजी से संख्या में बढ़ सकें। लेकिन उन्हें सूरज की रोशनी से दूर रखा जाता है और वे इस इमारत से बाहर नहीं निकल सकते। इस तरह एक नियंत्रित वातावरण में उनका पालन किया जाता है।

अजब-गजब | भारत का सबसे अनोखा जेल

यहां पैसे देकर बन सकते हैं कैदी, जानिए कितनी है एंट्री फीस

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग नए और अनोखे अनुभवों की तलाश में रहते हैं। कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स करता है, तो कोई अलग-अलग देशों की संस्कृति को करीब से समझने के लिए अलग-अलग जगह घूमने जाता है। लेकिन हाल के समय में एक ऐसा अनोखा और थोड़ा हैरान करने वाला ट्रेंड सामने आया है, जिसमें लोग पैसे देकर जेल का जीवन जीने का अनुभव ले रहे हैं। सुनने में यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन भारत के कुछ जेल प्रशासन ने पुराने और खाली पड़े हिस्सों को इस तरह विकसित किया है कि आम लोग वहां जाकर एक दिन के लिए कैदी जैसा जीवन महसूस कर सकें।

इस अनोखे प्रयोग में कुछ चुनिंदा जेलों में लोगों को अस्थायी रूप से कैदी की तरह रहने का मौका दिया जाता है। इसके लिए उन्हें एक तय शुल्क देना होता है। बदले में उन्हें जेल जैसा माहौल, कपड़े, खाना और दिनचर्या दी जाती है। हालांकि वे असली कैदी नहीं होते, लेकिन उन्हें वही अनुभव देने की कोशिश की जाती है जैसा एक कैदी को जेल में महसूस कराया जाता है।

उत्तराखंड की हल्द्वानी जेल इस प्रयोग के लिए काफी चर्चा में रही है। यहां जेल के पुराने और खाली हिस्से को इस तरह तैयार किया गया है कि आम लोग एक दिन के लिए वहां रुक सकें। आने वाले लोगों को अलग-अलग सेल में रखा जाता है, उन्हें जेल जैसी ड्रेस पहनाई जाती है और भोजन भी जेल की रसोई से ही मिलता है। पूरा वातावरण ऐसा बनाया जाता है कि व्यक्ति को असली जेल जैसा अनुभव हो सके। इस सुविधा का उद्देश्य लोगों को एक नया अनुभव देना बताया जाता है।

हल्द्वानी के इस जेल में एक दिन रुकने के लिए करीब 500 रुपये लिया जाता है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को एक अनोखा अनुभव देना है। इसे अक्सर डमी जेल एक्सपीरियंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति असली कैदी नहीं होता, लेकिन उसे जेल जैसा ही माहौल और दिनचर्या महसूस कराई जाती है। तेलंगाना की संगारेड्डी जेल का Feel the Jail प्रोग्राम तेलंगाना के मेदक जिले की संगारेड्डी जेल भी इसी तरह के एक खास प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। यहां पुराने केंद्रीय जेल को म्यूजियम में बदलकर Feel the Jail नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें लोग 24 घंटे तक जेल का जीवन जी सकते हैं।

इस अनुभव में लोगों को खादी के जेल यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, स्टील की प्लेट और बिस्तर उपलब्ध कराए जाते हैं और उन्हें जेल की रोजमर्रा की दिनचर्या अपनानी होती है। लोग बैरक साफ करते हैं, पौधे लगाते हैं और तय समय पर ही खाना खाते हैं। इससे उन्हें असली जेल जैसा ही सब कुछ लगता है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी पहले कुछ समय के लिए ऐसा प्रयोग किया गया था, जहां कुछ हिस्सों को टूरिस्ट सेल के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को जेल के जीवन के बारे में बताने का था।

राम माधव के बयान पर मचा घमासान

मोदी सरकार पर कांग्रेस का तीखा हमला

» भारत की संप्रभुता का अमेरिका में पीएम ने किया आत्मसमर्पण

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता राम माधव द्वारा अमेरिका में दिए गए एक विवादास्पद बयान ने भारत में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने भारत की संप्रभुता अमेरिका के हाथों गिरवी रख दी है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने पद पर बने रहने का अधिकार खो दिया है।

वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट को रिपोस्ट किया,जिसके मुताबिक, अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट केएक कार्यक्रम में माधव ने कहा था, ''भारत, ईरान से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया, अपने विपक्ष की आलोचना के बावजूद हम रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गए, भारत ने बिना अधिक कुछ कहे 50 फीसद टैरिफ पर भी सहमति दे दी, तो फिर भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए कहां पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहा है।'' बाद में माधव ने माफी मांग ली और कहा कि उनकी तरफ से गलत तथ्य रखा गया था।

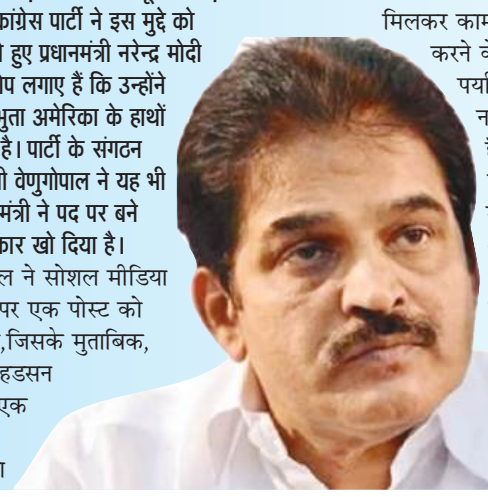

प्रधानमंत्री वाशिंगटन के इशारों पर काम कर रहे हैं : वेणुगोपाल

राष्ट्रीय सरेंडर संघ का फर्जी राष्ट्रवाद: राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस को राष्ट्रीय सरेंडर संघ कहा और संगठन को फर्जी करार दिया। राहुल गांधी ने एक पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रीय आत्मसमर्पण संघ। नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद। अमेरिका में सरासर चाटुकारिता। राम माधव ने संघ का असली चेहरा उजागर कर दिया है। गांधी की ये टिप्पणी वाशिंगटन डीसी में हडसन इंस्टीट्यूट के न्यू इंडिया सम्मेलन में राजदूत कर्ट कैंपबेल और एलिजाबेथ थ्रेलकेल्ड के साथ राम माधव की पैनल चर्चा में भाग लेने के बाद आई है। इस चर्चा में उन्होंने अमेरिका-भारत संबंधों के लिए नए रास्ते विषय पर बात की। चर्चा के दौरान, राम माधव ने भारत की ऊर्जा और व्यापार नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष की इतनी आलोचना के बावजूद भारत ईरान और रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया। भारत ने बिना ज्यादा कुछ कहे 50त्न टैरिफ पर सहमति जताई। तो आखिर भारत अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए पर्याप्त प्रयास कहाँ नहीं कर रहा है ?वेणुगोपाल ने दावा किया कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक समय था जब अमेरिका का सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में था और भारत ने हिम्मत नहीं हारी। आज का दिन है, जहां एक समझौतावादी प्रधानमंत्री ने भारत की संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी।

सम्राट चौधरी ने विश्वास मत जीता लालू प्रसाद यादव का किया जिक्र

» भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के पास 202 सीटों के साथ भारी बहुमत है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। चौधरी ने एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान यह प्रस्ताव पेश किया कि सदन राज्य की वर्तमान मंत्रिपरिषद पर अपना विश्वास बनाए रखे। 243 सदस्यीय सदन में यह प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया, जहां भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के पास 202 सीटों के साथ भारी बहुमत है। सत्ताधारी दल को जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित एनडीए के सहयोगियों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे विधानसभा में गठबंधन की संख्यात्मक शक्ति स्पष्ट हुई।

सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला और इस धारणा को खारिज कर दिया कि लोकतंत्र में नेतृत्व वंश या किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्राप्त होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक सत्ता जनता के जनादेश और निरंतर संघर्ष से मिलती है, न कि विरासत या व्यक्तिगत विशेषाधिकार से। अपनी राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा कि वे जनसमर्थन और दृढ़ता के बल पर शीर्ष पद तक पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का विशेष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौर की कठिनाइयों और कथित उत्पीड़न ने उनके राजनीतिक मार्ग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पदोन्नति सामूहिक राजनीतिक सहमति और पार्टी की एकता को दर्शाती है, और विशेष रूप से भाजपा की भूमिका को उजागर किया, जिसने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री के रूप में अवसर प्रदान किए। एक दिवसीय विशेष सत्र में सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। हालांकि, मतगणना की मांग न होने से यह संकेत मिलता है कि विपक्ष ने सदन में सरकार की संख्यात्मक शक्ति को सीधे चुनौती नहीं दी।

कमिंस की वापसी तय

» सनराइजर्स हैदराबाद का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच आज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 के 36वें मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद को राजस्थान रॉयल्स से भिड़ना है। इस मुकाबले से पहले हैदराबाद के लिए राहत भरी खबर आई है। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और इस मुकाबले में खेलते नजर आएंगे। पैट कमिंस का यह आईपीएल 2026 में पहला मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया, और अब उन्होंने कन्फर्म किया है कि वह राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे।

कमिंस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा, बहुत समय से इंतजार था, शनिवार वापसी करने के लिए बेताब हूं। कमिंस की गैरमौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने तेज गेंदबाजी अटैक में लगातार बदलाव किया है। शुरुआती मुकाबलों में हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट को आजमाने के बाद एसआरएच ने प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन को प्लेइंग इलेवन में जगह दी थी। हिंगे और साकिब ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए अपने डेब्यू मुकाबले में चार-चार विकेट चटकाए थे। पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में एसआरएच की कप्तानी की जिम्मेदारी ईशान किशन संभाल रहे हैं। आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक खेले 7 मुकाबलों में से 4 में जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। एसआरएच ने आखिरी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 47 रनों से जीत दर्ज की थी।

गुजरात को हराकर दूसरे नंबर पर पहुंची आरसीबी

बंगलूरू। शुक्रवार को आरसीबी और गुजरात टाइटंस जीटी के बीच खेला गया। विराट कोहली और देवदत पड्डिकल की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी ने मैच 5 विकेट से जीत लिया। पंजाब किंग्स छह मैचों में 11 अंक के साथ पहले स्थान पर है। आरसीबी सात मैचों में 10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स सात मैच में 10 अंक के साथ तीसरे स्थान, सनराइजर्स हैदराबाद सात मैचों में आठ अंक के साथ चौथे स्थान पर है। सीएसके सात मैच में छह अंक के साथ पांचवें स्थान पर है। जीटी के खिलाफ 81 रन की पारी खेल प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले विराट कोहली सीजन के शीर्ष स्कोरर बन गए हैं। विराट ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया है। विराट के सात मैचों में 328 रन हो गए हैं। अभिषेक 323 रन के साथ दूसरे और हेनरिक क्लासेन 320 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। पर्पल कैप पर चेन्नई के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज सात मैचों में 14 विकेट लिए हैं। लखनऊ के प्रिंस यादव सात मैचों में 13 विकेट के साथ दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा 12 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर हैं।

जमीन पर रातों-रात अवैध कब्जे की तैयारी

दोषियों के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। जानकीपुरम प्रथम वार्ड क्षेत्र में सरकारी संपत्ति पर अवैध खनन और निर्माण की कोशिश का मामला भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्र के अनुसार, 60 फीट रोड स्थित कुरैशी मीट शॉप के पीछे की जमीन, जो राज्य सरकार की बताई जा रही है, पर अज्ञात लोगों द्वारा रात के अंधेरे में खुदाई कर अवैध खनन किया गया।

इतना ही नहीं, बिना किसी अनुमति के डंपर लगाकर जमीन समतल करने और पक्का निर्माण करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। बताया गया है कि यह पूरी घटना 23 अप्रैल 2026 की रात को अंजाम दी गई। संगठन ने आरोप लगाया है कि सरकारी

भूमि पर इस तरह की गतिविधियां

» भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति ने डीएम को लिखा पत्र

कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कराई जाए और अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए जाएं।अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो सरकारी जमीन पर स्थायी कब्जा होने का खतरा बढ़ सकता है।

विपक्ष ने फिर खोला मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में अबतक के ऐतिहासिक मतदान के बीच विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की अपनी मुहिम की नई सिरे से शुरुआत की है। इसके लिए 13 विपक्षी दलों के 73 राज्यसभा सांसदों ने शुक्रवार को सीईसी को उनके पद से हटाए जाने के लिए ताजा नोटिस दिया है।

विपक्ष कुछ हफ्ते पहले ही सीईसी ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए इससे भी बड़ी कोशिश लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कर चुका है। लेकिन, राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने नोटिस के जांच के चरण में ही उसे स्वीकार्य नहीं किए जाने योग्य मानते हुए खारिज कर दिया।

जोन-8 हाउस टैक्स विभाग में गड़बड़झाला!

» कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ के जोन-8 स्थित हाउस टैक्स विभाग एक बार फिर विवादों में घिरा भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के नगर उपाध्यक्ष श्रीकांत वर्मा ने नगर आयुक्त को शिकायती पत्र सौंपते हुए विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार, हाउस टैक्स विभाग में तैनात कुछ कर्मचारी अपने मूल पद के विपरीत कार्य करते हुए अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरोप है कि ये कर्मचारी टैक्स निर्धारण और वसूली में अनियमितताएं करते हुए अवैध वसूली में लिप्त हैं।

शिकायत में जिन कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं, उनमें संजय यादव,प्रदीप कुमार,चंदन यादव,राजेश चौधरी शामिल हैं। श्रीकांत वर्मा का कहना है कि इन कर्मचारियों की कार्यशैली के कारण नगर निगम को भारी राजस्व हानि हो रही है और जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए समिति गठित की जाए। साथ ही, जांच पूरी होने तक आरोपित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से वर्तमान पद से हटाकर उनके मूल पद पर भेजा जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पवन खेड़ा की कानूनी लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस

पूरी पार्टी अपने नेता के साथ हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद फैसला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

गुवाहाटी। कांग्रेस ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद शनिवार को कहा कि वह अपने मीडिया विभाग के प्रमुख के साथ खड़ी है और उम्मीद जताई कि उत्पीड़न की राजनीति पर न्याय की जीत होगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, पूरी कांग्रेस अपने मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा के साथ मजबूती से एकजुट खड़ी है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि धमकी, डराने-धमकाने और उत्पीड़न की राजनीति पर न्याय की जीत होगी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह याचिका हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी पर कई पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां होने के आरोपों से जुड़े मामले में दायर की गई थी। मुख्यमंत्री शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने खेड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत

गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस थाने में आपराधिक मामले दर्ज कराए थे। इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खेड़ा को सात दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन असम पुलिस ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश पारित कर ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी थी और खेड़ा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने को कहा था।

जयराम रमेश ने दी जानकारी

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को भले ही अग्रिम जमानत के लिए देश भर की अदालतों में भटकना पड़ रहा हो, लेकिन उनकी पार्टी उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के राज्य सभा सांसद और महासचिव जयराम रमेश ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट करके यह जानकारी दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि पार्टी पवन खेड़ा को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में भी है। कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है कि पवन खेड़ा को न्याय दिलाने में वे सफल होंगे।

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर दर्ज हुई एफआईआर

- **महिलाओं पर विवादित बयान पड़ा भारी**
- **जदयू की प्रदेश सचिव ने की शिकायत**

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। राजनीति में आने वाली महिलाओं पर टिप्पणी मामले में पूर्णिया सांसद पर पटना के शास्त्रीनगर थाने में एफआईआर कराई गई है। जदयू की प्रदेश सचिव रीना कुमारी चौधरी ने यह मामला दर्ज कराया है। 20 एवं 21 अप्रैल को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दिए गए बयान को लेकर यह शिकायत की गई है।

शास्त्रीनगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि सांसद के बयान से आहत होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। सांसद ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान महिलाओं के खिलाफ बेहद अपमानजनक एवं अश्लील टिप्पणी की। जदयू प्रदेश सचिव ने शास्त्रीनगर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी इन बयानों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पप्पू यादव ने कहा कि 90 प्रतिशत महिलाएं राजनेताओं के कमरे में गए बिना राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकतीं। आगे यह घृणित आरोप लगाया कि राजनीतिमें काम करने वाली महिलाएं पुरुष नेताओं के साथ बिस्तर साझा करने के बाद ही प्रवेश और सफलता प्राप्त करती हैं। इन बयानों पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सही ठहराने का प्रयास किया। उनका यह बयान सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने वाली महिलाओं के चरित्र, आत्मसम्मान और सामाजिक गरिमा पर सीधा हमला है। सांसद ने न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि देश सेवा की आकांक्षा रखने वाली महिलाओं के लिए शत्रुतापूर्ण और निराशाजनक माहौल बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। बता दें कि पूर्णिया सांसद के बयान पर अलग-अलग मंचों पर विरोध हो रहा है। राज्य महिला आयोग ने भी उन्हें नोटिस दिया है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष से उनकी संसद की सदस्यता रद करने की मांग करने की बात भी कही है।

भाजपा बकासुर सब कुछ खा जाएगी : संजय राउत

शिवसेना यूबीटी के सांसद ने राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर की आलोचना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के सांसदों के हालिया दल-बदल को लेकर भाजपा की कड़ी आलोचना की और भाजपा को बकासुरों की पार्टी बताया, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती।

राउत ने राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के दो अन्य सांसदों की भाजपा में शामिल होने की निंदा की और भाजपा को बेशर्म करार देते हुए उसकी तुलना महाभारत के पौराणिक राक्षस बकासुर से की। संजय राउत ने कहा कि भाजपा की राजनीति सबको पता है। उनकी राजनीति को एक ही शब्द में कहा जा सकता है, बेशर्म। उन्हें जरा भी शर्म नहीं है। क्योंकि राघव चड्ढा जैसे लोग, जो कल तक हमारे मित्र थे, खुलेआम कहते थे कि भाजपा गुंडों, बदमाशों और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। ये सभी लोग थोक में गुंडों और भ्रष्ट लोगों की पार्टी में शामिल हो गए हैं... महाभारत में एक राक्षस है। उसका नाम बकासुर है। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती, उसका पेट कभी नहीं भरता। राउत ने आगे कहा कि भाजपा बकासुरों की पार्टी बन गई है। ये कुछ भी खा लेते हैं।

आने वाले दिनों में कहर बरपाएगी भीषण गर्मी

- **अल-नीनो, मई से होगा असर, अलर्ट**

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि एल नीनो की स्थिति मई से जुलाई के बीच विकसित हो सकती है, जिससे भारत समेत दक्षिण एशिया में मौसम पर बड़ा असर पड़ेगा। पहले अनुमान था कि यह स्थिति मानसून के दूसरे हिस्से (अगस्त-सितंबर) में बनेगी, लेकिन अब इसके जल्दी आने की संभावना जताई गई है।

एल नीनो एक ऐसी जलवायु स्थिति है, जो हर 2 से 7 साल में आती है और करीब 9 से 12 महीने तक रहती है। इसके कारण दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में तापमान और बारिश के पैटर्न बदल जाते हैं और आमतौर पर वैश्विक

तापमान बढ़ता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग पहले ही इस साल सामान्य से कम बारिश का अनुमान दे चुका है। डब्ल्यूएमओ के अनुसार, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे अगले महीने एल नीनो की स्थिति बनने के संकेत मिल रहे हैं।डब्ल्यूएमओ ने कहा है कि मई-जून-जुलाई के दौरान जमीन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। यानी लगभग हर जगह ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। संस्था का मानना है कि ऐसे मौसम पूर्वानुमान कृषि, जल प्रबंधन, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के लिए बेहद जरूरी होते हैं, ताकि समय रहते तैयारी की जा सके।

हिमालय में बर्फ कम, बढ़ी चिंता

रिपोर्ट के अनुसार, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में इस साल बर्फ की मात्रा सामान्य से 27.8प्रतिशत कम रही है, जो पिछले 20 सालों में सबसे कम है। इससे नदियों के पानी पर असर पड़ सकता है और करीब 2 अरब लोगों की जल सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आमतौर पर एल नीनो के दौरान ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के कुछ हिस्सों में कम बारिश या सूखे की स्थिति बनती है। वहीं दक्षिण अमेरिका, अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों और मध्य एशिया में ज्यादा बारिश देखने को मिलती है।

ईरान-अमेरिका में एक बार फिर शांति पर होगी चर्चा

- **जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बंपर उछाल**
- **16 प्रतिशत बढ़े दाम, 24 घंटे में होर्मुज से गुजरे सिर्फ 5 जहाज**

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। ईरान-यूएस-इसरायल युद्ध के सीजफायर के बीच भी मामला बीच-बीच में भड़क उठता है। जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बंपर उछाल आ गया है। 16प्रतिशत दाम बढ़ गए है। वहीं 24 घंटे में होर्मुज से सिर्फ 5 जहाज ही गुजरे हैं। उधर ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधी बातचीत के लिए शनिवार को अमेरिका का दल पाकिस्तान जायेगा।

व्हाइट हाउस ने बताया था कि युद्ध खत्म करने के प्रयासों के तहत दूत स्टीव विटकॉफ

और जेरेड कुशनर जाएंगे। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम को दो हफ्ते बढ़ाने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बुरी तरह घट गई है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 5 जहाज इस रास्ते से गुजरे, जबकि युद्ध से पहले रोज करीब 130 जहाज निकलते थे और इसमें एक भी बड़ा तेल टैंकर शामिल नहीं था। इस बाधा के चलते तेल की कीमतों में तेजी आई है, जहां ब्रेंट क्रूड इस हफ्ते करीब 16प्रतिशत तक बढ़ गया है। मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देलट्टी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक संबंध को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए फोन पर बातचीत की।

अमेरिका ने चीन की रिफाइनरी पर लगाया प्रतिबंध

अमेरिका ने चीन में स्थित एक रिफाइनरी और ईरान के तेल कारोबार से जुड़े कई जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका मकसद ईरान की तेल से होने वाली कमाई पर दबाव बढ़ाना है.ट्रेजरी विभाग ने कहा कि उसके ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय) ने हेंगली पेट्रोकेमिकल (डालियान) रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड को निशाना बनाया है. विभाग के अनुसार, यह कंपनी ईरान से कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वालों में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है।

अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की होगी बातचीत

मिडिल ईस्ट में जारी सीजफायर के बीच, शनिवार को ईरान और अमेरिका, पाकिस्तान में दूसरे दौर की शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप दूसरे दौर की वार्ता के लिए अपने दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को भेज रहे हैं, ईरान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अब्बास अराघची करेंगे। यह बातचीत ईरान-हिजबुल्लाह संघर्ष-विराम को तीन हफ्ते के लिए बढ़ाए जाने के एक दिन बाद हो रही है। हालांकि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले किए जाने के बाद शुरू हुआ युद्ध अभी खत्म होने के करीब भी नहीं दिख रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि दूत ईरानी प्रतिनिधियों के साथ आमने-सामने की बातचीत करेंगे, लेकिन ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि सीधी बातचीत की कोई योजना नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने फॉक्स न्यूज को बताया कि दोनों दूत अराघची के साथ बातचीत करेंगे। लेविट ने कहा, हमें उम्मीद है यह एक सार्थक बातचीत होगी और उम्मीद है कि इससे किसी समझौते की दिशा में प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद की यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन वह पूरी तरह बातचीत में शामिल रहेंगे।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। विधि सलाहकार: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा